(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या आकलन है तथा यह अन्य मूल्यांककों/आकलनकर्ता द्वारा किए गए आकलन से कितना भिन्न है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने हमारे देश के सकल घरेलू (देशीय) उत्पाद की वार्षिक विकास दर वर्ष 1998-99 के लिए 5.8 प्रतिशत आंकी है। अन्य अभिकरणों अर्थात राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, आर्थिक विकास संस्थान—दिल्ली अर्थशास्त्र विद्यालय, आर्थिक विकास संस्थान विकास योजना केन्द्र तथा भारतीय अर्थ-व्यवस्था निगरानी केन्द्र ने इसे अपने मूल्यांकनों में क्रमशः 5.3 प्रतिशत 6.1 प्रतिशत 5.00 प्रतिशत तथा 4.5 प्रतिशत दिया है।

Procurement of Cryogenic Space Rocket Engines

1074. SHRI AKHILESH DAS: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what progress has so far been made in pursuance of the deal for procurement of cryogenic space rocket engines from Russia to India; and

(b) how far, if at all, the delay in supply thereof has affected the space programme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI VASUNDHRA RAJE): (a) and (b) As per the modified agreement between ISRO and Glavkosmos, Russia, Glavkosmos has to supply a technological mock-up for ground use, a propellant filling mock-up for cryogenic stage filling trials before launch and 7 flight stages.

So far, technological mock-up and propellant filling mock-up and one flight stage have been received in India. The first flight stage has been received in september 1998 as against December 1996, envisaged at the time of modification of the agreement. Considering the amount of work involved in preparing the cryo stage for launch, the first flight of Geo-synchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) is now slated for the last quarter of 1999 on a success-oriented schedule.

Assistance to Manipur under Command Area Development Programme

1075. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the amount allotted to Manipur State under the Command Area Development Programme during the last five years;

(b) the details of programmes formulated under this scheme for all the districts of Manipur for current year; and

(c) by when these programmes are likely to be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): (a) An amount of Rs. 496.72 lakh has been released as central assistance during the last five years with effect from 1993-94 to 1997-98 to the Government of Manipur under the Centrally Sponsored Command Area Development Programme;

(b) Four irrigation projects of Manipur State are covered under the Centrally Sponsored Command Area Development Programme. The detail is given as under:

S. No.	Name of Irrigation Project covered under CAD Programme	Year of inclusion	Districts benefitted	Culturable Command Area under the project (ha.)
1.	Loktak CAD Project	1974-75	Manipur	24,000
2.	Sakmai Barrage Project	1983-84	Manipur	5,000
3.	Imphal Barrage Project	1993-94	Imphal & Thoubal	4,000
4.	Thoubal Multipurpose project	1995-96	Thoubal	4,000

(c) Central assistance is provided to the State Government on identified items of work on matching basis. As such completion of the programme depends upon the availability of funds under the State budget and the rate of execution of different activities of the programme by the State.

महाराष्ट्र और गुजरात में भूमिगत जल स्तर

1076. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी:**
श्रीचीमनभाई हरीभाई शुक्ला:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र और गुजरात के सूखा प्रवण जिलों में भूमिगत जल स्तर तेजी से गिर रहा है;

(क) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गिरते भूमिगत जल स्तर के बारे में केन्द्रीय भूजल बोर्ड के माध्यम से अद्यतन स्थिति की जांच कराई है; और

(घ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को इस प्रयोजन हेतु कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है; यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किये गये प्रेक्षणों के अनुसार, यह देखने में आया है कि महाराष्ट्र और गुजरात के सूखा प्रवण जिलों के कुछ भागों में भूजल स्तर में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है।

(ख) भूजल स्तर में गिरावट का जिला-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है **(नीचे देखिए)**

(ग) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड और राज्य भूजल संगठन (गुजरात जल संसाधन विकास निगम) ने गुजरात में भूजल स्तरों के खाली होने के बारे में अन्वेषण किए हैं। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने ऐसे अन्वेषण महाराष्ट्र में भी किए हैं।

(घ) इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को निधियां, प्रदान करने की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, सरकार ने सात राज्यों और दो संघ शासित क्षेत्रों जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के अध्ययनों के लिए वर्ष 1994-95 में प्रयोगिक आधार पर एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम शुरू की थी। गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में भूजल पुनर्भरण अध्ययनों पर 55.40 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। इस प्रयोगिक स्कीम के परिणामों से उत्साहित होकर सरकार ने अध्ययन करने संबंधी इस स्कीम को हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात सहित 11 अन्य राज्यों में लागू करने का निर्णय लिया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम की अनुमानित लागत 25 करोड़ रुपये है। गुजरात सरकार ने 359.58 करोड़ रुपये की ओ०ई०सी०एफ० (जापान) सहायता से राज्य के उत्तरी गुजरात क्षेत्र में अति-दोहित जलभृतों में सतही जल पुनर्भरण बढ़ाने के लिए एक स्कीम भी तैयार की है।